क्र० सं०	राज्य का नाम	डेयरी सहकारी समिति (संख्या)
16.	मिजोरम	सूचित नहीं किया
17.	नागालैण्ड	22
18.	उड़ीसा	1060
19.	पाण्डिचेरी	81
20.	पंजाब	6009
21.	राजस्थान	5128
22.	सिक्किम	122
23.	तमिल नाडु	8158
24.	त्रिपुरा	80
25.	उत्तर प्रदेश	9845
26.	पश्चिम बंगाल	1395
	कुल:	72744

विवरण-IV

गैर ऑपरेशन फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के तहत संस्वीकृत परियोजनाओं में संगठित/पुनर्गठित की जा रही डेयरी सहकारी समितियों की संख्या।

क्र० सं०	राज्य का नाम	डेयरी सहकारी समितियों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	180
2.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	15
3.	अरुणाचल प्रदेश	50
4.	असम	414
5.	बिहार	900
6.	गुजरात	240
7.	हरियाणा	75
8.	जम्मू और कश्मीर	517
9.	मध्य प्रदेश	516
10.	महाराष्ट्र	714
11.	मणिपुर	60
12.	मेघालय	36
13.	मिजोरम	46
14.	नागालैण्ड	80
15.	उड़ीसा	375
16.	सिक्किम	155
17.	तमिल नाडु	489
18.	त्रिपुरा	13
19.	उत्तर प्रदेश	1000
20.	पश्चिम बंगाल	240
	कुल:	6232

सिंचित तथा असिंचित भूमि के क्षेत्रफल में अन्तर

3953. **श्री राम जेठमलानी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में सिंचित भूमि तथा असिंचित भूमि के क्षेत्रफल तथा उसमें होने वाले औसत उत्पादन में भारी अंतर है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1995-96 में देश में सिंचित तथा असिंचित भूमि का पृथक-पृथक कितना-कितना क्षेत्रफल उपलब्ध था और उनकी उत्पादन क्षमता क्या-क्या थी तथा दोनों प्रकार की भूमि के उत्पादन में कितने प्रतिशत अंतर आंका गया है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) जी, हां।

(ख) 1992-93 के भू-उपयोग आंकड़ों (नवीनतम उपलब्ध) के अनुसार, देश में निवल बोए गए 142.51 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र में से 50.10 मिलियन हैक्टेयर भूमि सिंचित थी तथा 92.41 मिलियन हैक्टेयर भूमि असिंचित। देश में 1995-96 में सिंचित भूमि के 52 मिलियन हैक्टेयर होने का अनुमान लगाया गया था जो देश में बोए जाने वाले कुल निवल क्षेत्र का लगभग 36.5 प्रतिशत है।

सिंचित और असिंचित भूमि में होने वाली औसत उपज में जो अंतर होता है वह फसलों और क्षेत्र की भिन्नता के कारण होता है। असिंचित भूमि में होने वाली उपज की तुलना में सिंचित भूमि में होने वाली उपज औसतन 70 से 120 प्रतिशत तक अधिक है।

Loss due to inefficient utilisation of wagon

3954. SHRIMATI VEENA VERMA:
SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) what was the estimated loss to the Railways, zone-wise, during the last three years, year-wise, due to wasteful haulage and inefficient utilisation of wagon capacity and non-generation of earning capacity;

(b) what suggestions were given by the CAG and other consultative and advisory

bodies to improve the haulage and optimise the use of available wagon capacity; and

(c) the steps taken during the period for optimising earnings by better management of wagon capacity?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) to (c) Railways' Profit & Loss Accounts are maintained for the Zonal Railways as a whole and not separately for the various services such as Goods, Passengers, Parcels etc. The Profit & Loss Account of the nine Zonal Railways, zone-wise and year-wise for the last three years is given in the enclosed statement-I (*see* below) While a certain amount of empty haulage is inevitable in Railway operation, there has been a steady improvement in the figures of wagon utilisation vide Statement II (*see* below). Comptroller and Auditor General of India in their report for the year 1995 has commented upon the wagon utilisation on Indian Railways for the period 1990-91 to 1993-94. Year-wise details from 1990-91 to 1995-96 in respect of wagon utilisation indices viz., NTKM/wagon day, wagon kilometer/wagon day and wagon turnround are given in enclosed statement II (*see* below).

Improvement in wagon utilisation indices after 1993-94 has seen a quantum jump as compared to previous years. Continuous efforts are being made such as improving terminal management seeking cooperation of major users, cutting down avoidable delays and augmenting infrastructure inputs as may be necessary.

Statement-I

The profit earned/losses incurred by each Zonal Railways during the last three years, year-wise

PROFIT(+)/LOSS(−) *(Figures in crores of Rs.)*

Zone/Railway	*1993-94*	*1994-95*	*(1995-96)**
Central	*+655.66*	*+592.76*	*+537.92*
Eastern	*+15.96*	*+99.54*	*+2.15*
Northern	*+224.26*	*+396.16*	*+471.53*
N.E.	*−380.00*	*−419.61*	*−391.45*
N.F.	*−194.41*	*−213.33*	*−158.62*
Southern	*−205.97*	*−209.08*	*−182.86*
S.C.	*+211.55*	*+175.41*	*+304.48*
S.E.	*+1035.97*	*+1282.18*	*+1393.39*
Western	*+750.96*	*+1078.55*	*+1145.69*

(*) Provisional

Statement-II

Wagon Utilisation Indices for Indian Railways from 1990-91 to 1995-96

Year	NTKM/ Wagon day	% Variation	Wagon km/ Wagon day	% Variation
1990-91	1407		110.50	
1991-92	1439	2.3	113.20	3.5
1992-93	1457	1.2	116.40	2.4
1993-94	1506	3.3	125.00	7.4
1994-95	1590	5.6	138.50	10.8
1995-96	1754	10.3	148.10	6.9

Year	Wagon Turn Around	%Variations
1990-91	11.50	
1991-92	11.10	3.5
1992-93	10.83	2.4
1993-94	10.59	2.2
1994-95	9.89	6.6
1995-96	9.07	8.3

पूर्वोत्तर बिहार में केले की खेती

3955. **श्री नरेश यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर बिहार में बड़े पैमाने पर केले की खेती की जाती है और उसके उत्पादन में कैलशियम खाद की आवश्यकता होती है; और

(ख) क्या सरकार कैलशियम खाद की मांग के अनुपात में इसकी आपूर्ति कर रही है; यदि नहीं तो किसानों के हित में कैलशियम खाद की आपूर्ति हेतु सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की जा रही है?

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): (क) और (ख) जी, हां। पूर्वोत्तर बिहार में केले की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। कैलशियम की आवश्यकता को सुपर फास्फेट तथा मिश्रित उर्वरकों के उपयोग के माध्यम से पूरा किया जाता है। इसके अलावा, कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट को नाइट्रोजनी उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये उर्वरक विनियंत्रित हैं तथा बाजार में उपलब्ध हैं। रबी 1996-97 के दौरान बिहार में सुपर फास्फेट और कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट की अनुमानित आवश्यकता क्रमशः 1.0 और 0.75 लाख मीटरी टन है।

River Pollution in Karnataka

3956. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether some industries are causing pollution in rivers in Karnataka, if so, the names of such industries which are causing pollution and the names of rivers which are being polluted as a result thereof;

(b) whether Government have taken/ propose to take any action against such industries; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (CAPT. JAI NARAYAN PRASAD NISHAD): (a) There are some industries which are discharging their effluent after treatment into rivers. The treated effluent from these industries is generally conforming to the prescribed standards except for colour. However, certain stretches of the rivers on the down stream of the discharge points get polluted mainly during the lean flow season. The names of the industries and the rivers affected are:

Name of Industry	Name of river
1. M/s Harihar Poly Fibers, Dharwad	Tunga Bhadra
2. M/s Grasiline Division of Grasim Industries, Dharwad,	Tunga Bhadra
3. M/s Mysore Paper Mills, Bhadravati	Bhadra
4. M/s Mandya Paper Mills, Belagola	Cauvery